समक्ष राजीव नारायण रैना, जस्टिस

हेड टीचर, एम. जी. गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पंचोर-याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती अंगूरी और अन्य-उत्तरदाता

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 9375

03 मई, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227 - एक कर्मचारी की बहाली के बदले में श्रम न्यायालय द्वारा दी गई 50,000/- रुपये की मामूली राशि की राहत के खिलाफ राज्य द्वारा अपील-आयोजित, राज्य द्वारा एक तुच्छ याचिका एक साथी के प्रति हृदयहीनता और उदासीनता दिखाती है और औद्योगिक विवाद अधिनियम में वैधानिक कानून का भी उल्लंघन करती है-राज्य को मुकदमेबाजी के मामलों में अपने अधिकारियों की सनक और इच्छाओं के लिए अपने सार्वजनिक धन को पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, विद्वत श्रम न्यायालय ने बहाली से इनकार कर दिया है और छह वर्षों की प्रलेखित सेवा के लिए बहाली के बदले मुआवजे के रूप में केवल 50,000/- रुपये दिए हैं और फिर भी राज्य दुर्भाग्य से पुरस्कार से असंतुष्ट है। सिद्धांतः-पहले आई. डी. अधिनियम में वैधानिक कानून का उल्लंघन करते हैं, और फिर मामूली राशि के मुआवजे के साथ भाग जाते हैं, और फिर एक तुच्छ याचिका लाते हैं जो पूरी तरह से हृदयहीनता और एक साथी के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पटियाला बनाम आत्मा सिंह ग्रेवाल, (2014) 13 एस. सी. सी. 666 वाले मामले में राज्य द्वारा राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, 2010 को देखते हुए न्यायालयों में लाई गई गैर-जिम्मेदार मुकदमेबाजी और अनैतिक अपीलों पर उच्चतम न्यायालय ने गंभीर प्रतिकूल टिप्पणी की है।

(पैरा 5)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि आत्मा सिंह ग्रेवाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश को तितर-बितर करते हुए, इस परेशान करने वाली याचिका को ₹.50,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है जिसका भुगतान हरियाणा राज्य द्वारा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को दो माह की अवधि के भीतर किया जाना है और इस मामले में प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से जमा का प्रमाण निपटान के बाद उसके अभिलेख के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि डिफॉल्ट किया जाता है, तो डिफॉल्ट राशि में जमा होने तक 12% ब्याज होगा। (पैरा 7

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि लागत की राशि उन अधिकारियों से वसूल की जाएगी जिन्होंने आई. डी. अधिनियम में मूल वैधानिक सुरक्षा उपायों की अवज्ञा और उल्लंघन करके अंगूरी की छंटनी करने का निर्णय लिया और विभाग के उन अधिकारियों से जिन्होंने वर्तमान गैर-जिम्मेदाराना याचिका दायर करने का निर्णय लिया जिसमें दाखिल करने में शामिल लागत का भुगतान भी शामिल है।

(पैरा 10)

आर. टी. रेधु, डी. ए. जी., हरियाणा याचिकाकर्ता के लिए

राजीव नारायण रायना, न्यायमूर्ति,

(1) इस न्यायालय को इस बात का खेद है कि हरियाणा राज्य के शिक्षा विभाग ने 3 अक्टूबर, 2016 को घोषित विद्वत श्रम न्यायालय-I, गुरुग्राम के निर्णय के विरुद्ध यह तुच्छ याचिका प्रस्तुत की है, जो प्रत्यर्थी अंगूरी को बहाली के बदले में 50,000/- रुपये की मामूली राशि की राहत प्रदान करता है। 50, 000/- रुपये बचाने का प्रयास करने के लिए, राज्य ने हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका को दायर करने के लिए कहा है, भले ही एक भी तर्कपूर्ण आधार न हो, जिस पर अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन और असाधारण अधिकार क्षेत्र में पुरस्कार को बाधित किया जा सकता है।

(2) यह प्रत्यक्षतः एक तुच्छ रिट याचिका है जिसमें प्रत्यर्थी अंगुरी, जो कभी एक सरकारी प्राथमिक ग्राम विद्यालय में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था, की अवैध और प्रारंभ से ही शून्य समाप्ति शामिल है, जिसने अचानक कार्रवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय में छह साल की सेवा के बाद अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे एक छोटे से सीमांत श्रमिक को आजीविका से वंचित कर दिया, उसके फर्श की सफाई और सफाई की।

(3) विद्वत श्रम न्यायालय के समक्ष संदर्भ विचारण में रोजगार के संबंध को स्वीकार किया गया था।आवश्यक 240 दिनों के पूरा होने के मुद्दे को स्वीकार किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ('आईडीएक्ट') की धारा 25-एफ में शामिल छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का गैर-अनुपालन तब स्थापित किया गया था जब छंटनी मुआवजे का भुगतान समाप्ति के समय और उसके बाद भी नहीं किया गया था। डिपार्टमेंट स्कूल द्वारा विद्वत श्रम न्यायालय के समक्ष मामले को बचाव पक्ष की याचिका का समर्थन करने के लिए बिना किसी दस्तावेजी सबूत के बुरे आचरण और दुर्व्यवहार के स्तर तक बढ़ाने की मांग की गई थी।

(4) विद्वत श्रम न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि यदि वह सत्य था, तो न तो प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस द्वारा कामगार को उचित अवसर की पेशकश की गई थी और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की न्यूनतम गारंटी का पालन किया गया था, जो दिए गए कदाचार को स्थापित करने के लिए जांच के माध्यम से प्रक्रिया का पालन करता है। कदाचार के मौखिक आरोप न तो यहाँ हैं और न ही वहाँ, राज्य विभाग की ओर से, "छंटनी के कारणों का संकेत दिए बिना" समाप्ति को सही ठहराने के लिए, जो आईडी अधिनियम की धारा 25 एफ (ए) में निहित विषयगत तंत्र का हिस्सा है। रोजगार में भाड़े और आग की योजना एक प्राचीन सिद्धांत है।

(5) अंगुरी पर दुराचार का आरोप लगाने में याचिका दायर करने वाले प्रबंधन का तर्क निम्न न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, लेकिन विद्वत श्रम न्यायालय से पूर्ण कानूनी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सही ढंग से विफल रहा, यह मानते हुए कि समाप्ति न तो उचित थी और न ही उचित थी और यही तर्क इस न्यायालय के समक्ष भी विद्वत विधि अधिकारी को दी गई सुनवाई के दौरान विफल हो गया। इसके बाद यह कहा गया कि

इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कुछ भी नहीं है। विद्वत श्रम न्यायालय ने बहाली से इनकार कर दिया है और छह साल की प्रलेखित सेवा के लिए बहाली के बदले मुआवजे के रूप में केवल 50,000/- रुपये दिए हैं और फिर भी राज्य दुर्भाग्य से पुरस्कार से असंतुष्ट है। सिद्धांतः-पहले आई. डी. अधिनियम में वैधानिक कानून का उल्लंघन करते हैं, और फिर मामूली राशि के मुआवजे के साथ भाग जाते हैं, और फिर एक तुच्छ याचिका लाते हैं जो पूरी तरह से हृदयहीनता और एक साथी के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पटियाला बनाम आत्मा सिंह ग्रेवाल मामले में राज्य द्वारा राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, 2010 के सामने अदालतों में लाई गई गैर-जिम्मेदाराना मुकदमेबाजी और अनैतिक अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर प्रतिकूल टिप्पणी की है।

(6) राज्य को मुकदमेबाजी के मामलों में अपने अधिकारियों की सनक और इच्छाओं के अनुसार अपने सार्वजनिक धन को वहन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को अपनी संक्षिप्त स्मृति में आत्मा सिंह ग्रेवाल मामले में टिप्पणियों को याद दिलाने की आवश्यकता है, जो उद्धरणों में पुनः प्रस्तुत किए जाने योग्य हैंः-

"14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब किसी मामले का फैसला किसी पक्ष के पक्ष में किया जाता है, तो अदालत उसके पक्ष में खर्च भी तय कर सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की लागत वास्तविक और प्रतिपूरक शर्तों में होनी चाहिए न कि केवल प्रतीकात्मक। अनुकरणीय लागत भी हो सकती है जब अपील पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित हो। [रामरामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी देखें। हालांकि, सवाल यह है कि क्या केवल लागत लगाना ही निवारक साबित होगा? हम ऐसा नहीं सोचते। हमारा दृढ़ मत है कि अकेले राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों पर लागत लगाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अपील दायर करने के लिए इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना निर्णय लेने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि लागत, यदि लगाई जाती है, तो सरकार के खजाने से आती है। इसलिए, अगला कदम उठाने का समय आ गया है जो ऐसे अधिकारियों से लागत की वसूली है जो अपील दायर करने के ऐसे तुच्छ निर्णय लेते हैं, यह अच्छी तरह से जानने के बाद भी कि ये पूरी तरह से परेशान करने वाले और अपील के लिए अनावश्यक हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि संबंधित अधिकारी से लागत की वसूली का ऐसा आदेश केवल उन मामलों में पारित किया जाना चाहिए जहां अपील को प्रत्यक्ष रूप से तुच्छ पाया जाता है और अपील दायर करने का निर्णय भी स्पष्ट रूप से तर्कहीन और अनावश्यक पाया जाता है।

15. वर्तमान जैसे मामले में, जहां संबंधित अधिकारी ने अपील दायर करने का निर्णय लिया था, उससे लागत वसूलने के उच्च न्यायालय के निर्देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे अधिकारियों पर जिम्मेदारी की भावना तभी आएगी जब उन्हें सरकारी खजाने पर बोझ डालने के बजाय अपनी जेब से लागत का भुगतान करना होगा।

16. इसलिए हम संबंधित अधिकारी से लागत की वसूली के लिए उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश को वापस लेने के इच्छुक नहीं हैं। 10, 000 रुपये की अतिरिक्त लागत के साथ खारिज कर दिया गया।

(7) आत्मा सिंह ग्रेवाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश को तितर-बितर करते हुए, इस परेशान करने वाली याचिका को हरियाणा राज्य द्वारा पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को दो महीने की अवधि के भीतर 50,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है और निपटान के बाद

इसके रिकॉर्ड के लिए इस मामले में प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से जमा का प्रमाण रखा जाता है। यदि डिफॉल्ट किया जाता है, तो डिफॉल्ट राशि में जमा होने तक 12% ब्याज होगा।

(8) मैं कामगार को मुआवजे की राशि का मिलान करने के लिए लागत प्रदान करता, लेकिन ऐसा करने से बचता क्योंकि याचिका की बर्खास्तगी सीमित है क्योंकि अंगूरी को नोटिस जारी नहीं किया गया था क्योंकि यह उचित नहीं पाया गया था। कल्पना कीजिए, हरियाणा राज्य को उम्मीद थी कि अंगूरी को 50,000 रुपये का बचाव करने के लिए मुकदमे में पैसा खर्च करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इससे अधिक कठोर रवैया और क्या हो सकता है, मैं सोचने की हिम्मत नहीं करता।

(9) इस याचिका के खारिज होने के साथ, इस न्यायालय में लाई गई चुनौती के मामले में, प्रत्यर्थी के अधिकार, यदि कोई हों, पुरस्कार के खिलाफ खुले रखे जाते हैं। मैं दी गई राहत के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करता, क्योंकि इससे अन्य प्रत्यर्थी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता का अध्याय बंद हो गया है।

(10) लागत की राशि उन अधिकारियों से वसूल की जाएगी जिन्होंने आईडी अधिनियम में मूल वैधानिक सुरक्षा उपायों की अवज्ञा और उल्लंघन करके अंगूरी को फिर से निकालने का निर्णय लिया और विभाग के उन अधिकारियों से जिन्होंने वर्तमान गैर-जिम्मेदाराना याचिका दायर करने का निर्णय लिया, जिसमें दाखिल करने में शामिल लागत का भुगतान भी शामिल है।

(11) इस आदेश की एक प्रति कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा को भेजी जाए ताकि इस न्यायालय में राज्य द्वारा लापरवाह मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके।